ग्रेटर निगम में बोर्ड कार्यकाल खत्म होने के 9 दिन पहले 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाने पर विवाद शुरू

उपमहापौर पुनीत कर्णावट और स्वच्छता चेयरमैन अभय पुरोहित ने महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर को पत्र लिखकर आपत्ति जताई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। महज 9 दिन बाद जयपुर के ग्रेटर और हैरिटेज निगम के बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसी बीच ग्रेटर निगम में महज 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर कार्यकारिणी बैठक (ई.सी. मीटिंग) बुलाने पर विवाद शुरू हो गया है। उपमहापौर पुनीत कर्णावट से लेकर सफाई समिति के चेयरमैन अभय पुरोहित ने महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी, कांग्रेस नेता और नगर निगम के पूर्व सचेतक रहे गिरिराज खंडेलवाल और भाजपा-कांग्रेस के पार्षदों ने भी इसे नगरपालिका एक्ट का खुला उल्लंघन बताते हुए महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है।

सूत्रों की मानें तो 31 अक्टूबर को नगर निगम जयपुर ग्रेटर की कार्यकारिणी सभा का 68 प्रस्तावों का 140 पृष्ठ का एजेंडा कथित तौर पर जारी किया गया है, जिसमें कार्यकारिणी समिति की सभा का आयोजन शनिवार 1 नवंबर को सायं 4 बजे निर्धारित बताया गया।

जैसे ही यह एजेंडा कुछ पार्षदों और चेयरमैनों के पास पहुंचा तो उन्होंने इस पर आपत्ति जता दी। चेयरमैन अभय पुरोहित ने महापौर को पत्र लिखकर कहा कि, नियमानुसार 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को ई.सी. की मीटिंग की सूचना देनी होती है, आखिर 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस यह बैठक क्यों बुलाई जा रही है। जबकि यह एजेंडा अभी तक किसी भी कार्यकारिणी सदस्य तक नहीं पहुंचा है।

अभय पुरोहित ने लिखा कि, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के आज्ञा परख प्रावधानों तथा संबंधित नियमों के अनुसार कार्यकारिणी सभा बुलाने के लिए सदस्यों को न्यूनतम 7 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है। वर्तमान स्थिति में,

■ **कांग्रेस नेता गिरिराज खंडेलवाल, नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी से लेकर भाजपा-कांग्रेस के पार्षदों ने नगरपालिका एक्ट का खुला उल्लंघन बताया**

एजेंडा जारी करने की तिथि और बैठक की तिथि के बीच 24 घंटे से भी कम समय का अंतर है, जो स्पष्ट रूप से वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में बुलाई गई सभा और उसमें लिए गए किसी भी निर्णय को कानूनी वैधता या बाध्यता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यह प्रक्रिया विधि-विरुद्ध है।

अतः यह आवश्यक है कि उक्त बैठक को निरस्त कर, नियमों के अनुरूप 7 दिन का नोटिस अवधि पूर्ण करते हुए 6 या 7 नवंबर को सभा का आयोजन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी सदस्यों को विधिवत तैयारी एवं सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके।

इस बारे में जब उपमहापौर पुनीत कर्णावट से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि, मुझे भी कुछ पार्षदों से ज्ञात हुआ है कि 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इतने कम समय में आखिर 68 प्रस्तावों का एजेंडे के साथ बैठक क्यों बुलाई जा रही है, यह समझ से परे है।

नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि, राजस्थान नगर पालिका एक्ट में साफ प्रावधान है कि 7 दिन के नोटिस पर ही कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई जा सकती है, ताकि सभी सदस्य तैयारी कर सकें और प्रस्तावों पर विधिवत चर्चा हो सके। परंतु ग्रेटर नगर निगम में तो महापौर की मनमानी चल रही है। ऐसा लगता है कि महापौर 68 प्रस्तावों को छिपाकर जल्दबाज़ी में पारित करवाना चाह रही है। हम मांग करते हैं कि 1 नवंबर 2025 को प्रस्तावित कार्यकारिणी सभा को तत्काल निरस्त किया जाए और नियमानुसार 6 या 7 नवंबर को नई तिथि घोषित की जाए।

वहीं कांग्रेस नेता और नगर निगम के पूर्व मुख्य सचेतक रहे गिरिराज खंडेलवाल ने भी 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर बुलाई गई ई.सी. मीटिंग को अवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मनमानी कर रही है। खंडेलवाल ने कहा कि, अचानक क्या आवश्यकता पड़ गई कि 24 घंटे के नोटिस पर कार्यकारिणी मीटिंग पड़ गई, क्या इसमें क्या कोई निजी स्वार्थ है। उन्होंने कहा कि महापौर बिना किसी सूचना के एक सप्ताह दुबई में जाकर आई है, परंतु इसकी जानकारी ना तो कमिश्नर को है और ना ही सरकार को। जयपुर पहुंचते ही महापौर ने जिस प्रकार आनन-फानन में नगर निगम ग्रेटर की कार्यकारिणी बैठक बुलाने की घोषणा की गई है, वह पूर्णतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं संबंधित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

ईडब्ल्यूएस को अंकों में छूट नहीं देने पर जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने यूजीसी की ओर से आयोजित नेट परीक्षा-2025 में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को अंकों में छूट नहीं देने पर केन्द्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए। याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि यूजीसी की ओर से आगामी दिसंबर माह में नेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिसमें स्नातकोत्तर में 55 फीसदी अंक लाने वालों को पात्र माना गया है। वहीं इसके लिए एससी, एसटी और ओबीसी सहित अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच फीसदी अंकों की छूट दी गई है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के 53 फीसदी अंक हैं और वह ईडब्ल्यूएस वर्ग का है। इसके बावजूद उसे पांच फीसदी अंकों की छूट नहीं दी जा रही है। याचिका में गुहार की गई है कि नेट परीक्षा के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

आरएसएस पर प्रतिबंध की बात करना सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति : सी.पी.जोशी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौडगढ़ सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की मांग को घोर आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और देश की राष्ट्रवादी भावना के विरुद्ध बताया है। सांसद सीपी जोशी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, शिक्षा, सेवा और संस्कार के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। देश में संकट के समय बाढ़, भूकंप, महामारी या कोई आपदा हो, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले सेवा के लिए आगे आते हैं। ऐसे संगठन को प्रतिबंधित करने की बात करना देश की जन भावनाओं का अपमान है। कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान दर्शाता है कि कांग्रेस आज भी उसी मानसिकता से ग्रसित है, जिसने देश को विभाजित किया और समाज में वैमनस्य फैलाया।

सांसद जोशी ने कहा कि खडगे को इतिहास की जानकारी ताज़ा करनी चाहिए। वर्ष 1949 में कांग्रेस सरकार ने ही संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। इतना ही नहीं, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आरएसएस की देशभक्ति और योगदान की सराहना की थी। संघ के स्वयंसेवकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रसद और अन्य सहायता पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में नेहरू ने स्वयं आरएसएस को आमंत्रित किया था, यह संघ की राष्ट्र सेवा की मान्यता थी।उसी संघ के मूल्यों और अनुशासन से प्रेरित होकर आज भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सांसद सीपी जोशी ने कहा कि अराजकता और अस्थिरता कांग्रेस की असली पहचान बन चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वर्तमान में जहां भी कांग्रेस की सरकारें है, खडगे वहां की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। पूर्व गहलोत सरकार के शासनकाल में राजस्थान बलात्कार, लूट, और हत्या की घटनाओं में देश में टॉप पर पहुंच गया था, विधानसभा चुनाव के समय खडगे ने राजस्थान में आकर आरएसएस को खूब कोसा था जिसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने कांग्रेस शासन को उखाड़ फैंका। सांसद जोशी ने कहा सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों का विलय किया। किंतु कश्मीर रियासत की जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने पास रखी थी, वहां नेहरू ने धारा 370 लगाकर कश्मीर को भारत से अलग-थलग करने का प्रयास किया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बना, जिससे वास्तव में सरदार पटेल का सपना साकार हुआ।

'सहकार से समृद्धि' पहल लागू करने में राजस्थान कर रहा है बेहतरीन कार्य

केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय ने समीक्षा बैठक में पुनः की प्रदेश की सराहना

जयपुर। 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राजस्थान में बेहतरीन कार्य हो रहा है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने पहलों को क्रियान्वित करने में उल्लेखनीय कार्य करने पर राज्य की सराहना की।

सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पंकज बंसल की अध्यक्षता तथा संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शुक्रवार को वीसी के माध्यम से 'सहकार से समृद्धि' की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां विश्व मोहन शर्मा एवं सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नेहरू सहकार भवन से वीसी के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए।

■ **'राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 171 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है'**

सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पंकज बंसल की अध्यक्षता तथा संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शुक्रवार को 'सहकार से समृद्धि' की समीक्षा बैठक हुई।

मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बंसल ने कहा कि नवीन एम-पैक्स गठन की दिशा में राजस्थान में बेहतरीन कार्य हुआ है। राज्य में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक एम-पैक्स का गठन किया गया है और इस मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने विश्व की वृहद् अन्न भण्डारण योजना तथा राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता के मामले में उल्लेखनीय कार्य करने पर राज्य की सराहना की। साथ ही, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी राज्य की तारीफ की।

बैठक में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 171 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 104 गोदामों का निर्माण कार्य शुरू कर 70 गोदामों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन 18 गोदामों का कार्य 15 दिवस में तथा 11 गोदामों का निर्माण कार्य नवम्बर माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

रजिस्ट्रार ने बताया कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना के अंतर्गत राज्य की 5 हजार 614 पैक्स में डे-एंड किया जा चुका है तथा 31 दिसम्बर तक सभी पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन कार्य पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि किसानों को ऋण वितरण के मामले में देश में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन राजस्थान में हुए हैं। अब तक राज्य की 6083 समितियों द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के लिए आवेदन किया जा चुका है। इस मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं, 957 समितियों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं 1018 समितियों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्यता के लिए आवेदन किया गया है।

उन्होंने बताया कि इन बहुराज्यीय समितियों द्वारा दिसम्बर माह के अंत तक राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां आरम्भ कर दी जाएंगी। राज्य की सभी पैक्स को इन समितियों का सदस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में 'सहकार से समृद्धि' की अन्य पहलों की भी समीक्षा करते हुए इनकी क्रियान्विति में गति लाने तथा समयबद्ध रूप से लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

सार-समाचार

एटक ने 106वां स्थापना दिवस मनाया

जयपुर। राज्य कार्यालय स्वामी कुमारानन्द पर झंडारोहण के साथ अखिल भारतीय ट्रेडयूनियन काँग्रेस (एटक) ने अपना 106वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एटक के कार्यकारी अध्यक्ष डी.के.छंगाणी ने कार्यालय पर झंडारोहण किया। छंगाणी ने अपने उद्बोधन में एटक का इतिहास बताया और श्रमिकों को अपना दायित्व निभाने के लिए कहा। एटक के राज्य सचिव व राजस्थान रोडवेज़ यूनियन के महासचिव धर्मवीर सिंह ने कहा कि श्रमिकों को अपनी यूनियनों व माँगों के अलावा अपने नागरिक दायित्वों को भी समझना चाहिए।उन्होंने कहा कि आज नागरिकों के संविधानिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है इससे सबसे ज़्यादा नुक़सान श्रमिकों का होगा। सभा को भाकपा के ज़िला सचिव रमेश शर्मा, शान्ति एवं एकजुटता संगठन की महासचिव सुनीता चतुर्वेदी, बिजली वर्क्स फेडरेशन के नेता गिरधारीलाल मीणा,व बनवारीलाल, सुरक्षा उपकरण निर्माण क्षेत्र आर.एस.राठौड़, लेयर हाउसिंग कर्मचारियों के नेता कुलदीप सिंह, एटक के कोषाध्यक्ष विनोद राय, असंगठित कर्मचारियों के नेता शरीफ़, रोडवेज़ यूनियन के सुरेंद्र मोहन सक्सेना एवं बिजली वर्कर्स यूनियन के महासचिव केशव ने संबोधित किया।

एमवे अध्यक्ष ने किया भारत दौरा

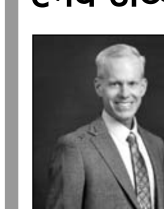

जयपुर। एमवे के अध्यक्ष और सीईओ माइकल नेल्सन ने कंपनी की विनिर्माण यात्रा के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सप्ताह भारत का दौरा किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो एमवे के वैश्विक संचालन में भारत की रणनीतिक भूमिका को मजबूत करता है - भारत, अमेरिका और चीन के साथ एमवे के केवल तीन वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक है। इस मजबूत नींव पर निर्माण करते हुए, कंपनी अगले तीन से पाँच सालों में 100 करोड़ रुपये (12 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करेगी ताकि एमवे बिज़नेस ओनर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्षमताओं को और मजबूत किया जा सके, अपनी भौतिक उपस्थिति का विस्तार किया जा सके, और ग्राहक अनुभव को बढ़ाया जा सके। यह नेल्सन का भारत में अध्यक्ष और सीईओ बनने के बाद पहला दौरा है, जो एमवे की वैश्विक विकास रणनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है और इस क्षेत्र में कंपनी की समावेशी एवं सतत प्रगति के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराता है।

ओ.बी.सी. आयोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम

जयपुर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग द्वारा संचालित सर्वे कार्य के संबंध में शुक्रवार दोपहर 2 से 4 बजे तक प्रशिक्षण के प्रथम फेज में राज्य के 21 जिलों भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीडवाना-कुचामन, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, फलोदी, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सलूम्बर, सीकर, टोंक, उदयपुर के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलों के अति. कलेक्टर, जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी / सहायक नोडल अधिकारी, संदर्भ व्यक्ति (मास्टर ट्रेनर्स), तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की, जिसमें सभी सहभागियों को राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के द्वारा सर्वे कार्य के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। आयोग के सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन के अनुसार इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सर्वे कार्य की रूपरेखा, प्रक्रिया तथा आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की जानकारी प्रदान करना रहा। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी अब अपने-अपने जिलों में सर्वे कार्य हेतु नियुक्त प्रगणकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे कार्य को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपादित किया जा सके।

स्वदेशी मल्टीमीडिया सब-सिस्टम शुरू

जयपुर। भारत ने आज स्वदेशी दूरसंचार तकनीक के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। दूरसंचार विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए यह गर्व का क्षण रहा, जब डॉ. नीरज मित्तल, सचिव (टेलीकॉम) एवं चेयरमैन, डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमीशन, भारत सरकार ने जोधपुर में सी-डॉट द्वारा विकसित स्वदेशी मल्टीमीडिया सब- सिस्टम का शुभारंभ किया। सी-डॉट द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म टीसीएस के सहयोग से एकीकृत किया गया है, जो राजस्थान के 4जी नेटवर्क को और अधिक सशक्त बनाएगा। इसके माध्यम से ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली वॉयस और तेज़ डेटा सेवाएं प्राप्त होंगी। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीया, दूरसंचार (सीजीएमटी), बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल, तथा बीएसएनएल राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सुरीले गीतों से आज सजेगी महफिल

जयपुर। संगीत ग्रुप अरुणाज़ गीत गाता चल की ओर से शनिवार 1 नवम्बर, 2025 को गा मेरे मन गा -सीजन 5 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इम्मोर्टल एस जे शीर्षक से होनेवाला गा मेरे मन गा - सीजन 5 मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध गीतों को समर्पित रहेगा। कार्यक्रम में उनके सुपर हिट संगीत से सजे एकल और युगल गीतों की महफ़िल सजाई जाएगी। श्रोता बॉलीवुड गीतों के स्वर्णकाल कहे जाने वाले दौर के लगभग 30 मीठे-मधुर गीतों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। कार्यक्रम में 1950, 1960 और 1970 के दशक के चुनिंदा गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। यह कार्यक्रम शाम साढ़े पाँच बजे जवाहर कला केन्द्र के रंगायन सभागार में होगा। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कार्यक्रम में टाइम बैंक ऑफ़ इण्डिया की सक्रिय भागीदारी रहेगी।

मिलने के बहाने बुलाकर मंगेतर ने किया दुष्कर्म

जयपुर। मानसरोवर थाना इलाके में एक युवती ने अपने ही मंगेतर के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर पर आरोपी मंगेतर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

थानाधिकारी लखन सिंह खटाना ने बताया कि थाना इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने मामला दर्ज कराया है कि कुछ महीने पहले उसकी सगाई आरोपी से हुई थी। सगाई के बाद मंगेतर से उसकी बातचीत होती रहती थी। मई-2025 में मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने जल्दी ही शादी होने की बात कहीं, पीड़िता ने मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए धमकी दी। कुछ दिन पूर्व आरोपी ने युवती को मिलने बुलाया और झगड़ा करते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। खुद के साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलने पर पीड़ित युवती थाने पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

युवाओं के लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं सराहनीय : फेलिपे

संयुक्त राष्ट्र के युवा मामलों के सहायक महानिदेशक डॉ. फेलिपे का स्वागत शासन सचिव एवं राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. नीरज के. पवन ने किया।

जयपुर (कासं)। संयुक्त राष्ट्र के युवा मामलों के सहायक महानिदेशक डॉ. फेलिपे ने राजस्थान युवा बोर्ड तथा युवा मामले एवं खेल विभाग का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं की विभिन्न योजनाएं सराहनीय हैं।

इस अवसर पर विभाग की शासन सचिव एवं राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. नीरज के. पवन ने राज्य में युवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में युवा सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए कई नवाचारात्मक पहल की जा रही हैं, जिनमें युवा साथी केन्द्र, युवा क्लब और राजस्थान युवा नीति 2025 प्रमुख हैं। यूएनएफपीए के राज्य प्रमुख डॉ. दीपेश गुप्ता ने बताया कि नई युवा नीति के तहत युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें कौशल विकास, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य और नेतृत्व विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। डॉ. रुशभ ने युवा साथी केन्द्रों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन केन्द्रों के माध्यम से युवाओं को मानसिक एवं करियर परामर्श (काउंसलिंग) प्रदान की जा रही है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना कर सकें।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. फेलिपे को युवा आइकॉन से संवाद का अवसर मिला, जिसमें राज्य के प्रेरणादायक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। उन्हें राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से भी परिचित कराया गया।

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से संवाद किया और युवाओं के खेल एवं फिटनेस के क्षेत्र में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की।

केन्द्रीय अपर सचिव डॉ. वर्षा जोशी ने ली पशुपालन विभाग के अफसरों की बैठक

केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने पर दिया बल

जयपुर (कासं)। भारत सरकार की अपर सचिव (पशुपालन) डॉ. वर्षा जोशी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित सभा कक्ष मंथन में राजस्थान पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में विभागीय योजनाओं, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

अपर सचिव ने राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन पर बोलते हुए कहा कि इस इंटीग्रेटेड आई टी इकोसिस्टम को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों तक तकनीक समर्थित प्रणाली के माध्यम से विभाग की बेहतर जानकारी उपलब्ध कराना है। जिससे कम समय में अधिक आउटपुट मिल सके। राजस्थान जैसे पशुधन प्रधान राज्य में एनडीएलएम के माध्यम से पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालकों की आय बेहतर करने और पशुओं तथा पशु उत्पादों की ट्रेसिब्लिटी में बहुत मदद मिल सकती है। डॉ जोशी ने अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर नियमित निगरानी और फील्ड विजिट बढ़ाने पर भी बल दिया।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन,और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गति लाई जाए तथा किसानों और पशुपालकों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से पहुँचाया जाए। उन्होंने राज्य सरकार की नवाचारपरक पहल 'सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक' और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' की भी सराहना की। इससे पूर्व डॉ. जोशी ने जयपुर में बस्सी स्थित सीमन बैंक का दौरा कर सीमन बैंक की कार्यप्रणाली, संरचना तथा सीमन संरक्षण एवं उत्पादन की प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया।

भारत सरकार की अपर सचिव पशुपालन डॉ. वर्षा जोशी ने शुक्रवार को सचिवालय में राजस्थान पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

डॉ. जोशी ने अधिकारियों से सीमन बैंक की तकनीकी व्यवस्था, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली तथा नस्ल सुधार कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीमन उत्पादन और वितरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अपर सचिव ने सीमन बैंक में कार्यरत वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों से संवाद करते हुए अनुसंधान और नवाचार को पशुधन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय से नस्ल सुधार कार्यक्रमों को और सशक्त बनाने पर बल दिया। डॉ समित शर्मा, शासन सचिव, पशुपालन व गोपालन ने राजस्थान में पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और विभाग की प्रगति के बारे में अवगत कराया। बैठक में शासन सचिव पशुपालन डॉ. समित शर्मा, वी.जयचंद भानु रेड्डी, निदेशक पशुपालन निदेशालय, केद्र सरकार, डॉ. भूषण त्यागी, संयुक्त आयुक्त पशुपालन निदेशालय केंद्र सरकार सहित अन्य अधिकारी, आरसीडीएफ महाप्रबंधक श्रुति भारद्वाज तथा निदेशक पशुपालन, राजस्थान डॉ आनंद सेजरा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।